[डा० भाई महावीर]

दो बातों का जिक्र मुझे करना है। 12 लाख रु० विधवाओं, वृद्ध पुरुषों और दूसरे लोगों के लिए, अपंग लोगों के लिए, देने का प्रस्ताव था, वह स्वीकार नहीं किया। इन्जीनियरिंग कालेज के टेक्निकल कर्मचारियों की हड़ताल चल रही है, मैं उस कालेज की गवर्निग बाडी में था। उस समय गवर्निग बाडी ने उनके वेतन को बढ़ाने के प्रस्ताव दिल्ली एड्मिनिस्ट्रेशन को भेजे। एड्मिनिस्ट्रेशन नें केन्द्र सरकार को भेजा हुआ है। महीनों से उन प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार निर्णय नहीं कर सकी। छोटे-छोटे कर्मचारी है, उनका वेतन सवा सौ, डेढ़ सौ रुपए हैं और 1947 से उनके वेतन नहीं बढ़े।

ऐसी स्थिति में दिल्ली की कितनी उपेक्षा हो रही है इसको ध्यान में रख कर मैं कहता हूं इस बिल को स्वीकार करें और ऐसा करके सरकार उदारता का ही परिचय नहीं, अपनी लोकतांत्रिक वृद्धि का परिचय दे सकती है। अगर आपने नही दिया तो आप अपने स्थान पर बैठे हुए अपने आप को बड़ी बधाई लायक समझते हैं तो मुझे अफसोस है मैं आपको बधाई नहीं दे सकता हूं। इस बात का मुझे खेद है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM SAHAI) :The question is :

> "That the Bill further to amend the Delhi Administration Act, 1966, be taken into consideration."

The motion was negatived.

THE FOREIGNERS (AMENDMENT) BILL 1968

श्री मानसिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विदेशी अधिनियम, 1946 का सशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपसभाध्यक्ष (श्री राम सहाय) : अब 5 बज गए हैं।

RE RAJYA SABHA MEMBER ARRESTED AND RELEASED

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAM SAHAI) : I have to inform Members that the following telegram dated the 24th August, 1972, has been received from the City Magistrate, Kanpur :—

> "Shri Prem Manohar Member Rajya Sabha who was arrested on 16th August for Defiance of Prohibitory orders U/S 144 Cr. P.C. was tried by me today 23rd August (—) he was convicted U/S 188 IPC on pleading guilty and released after serving imprisonment till rising of Court (—)

5 P.M.

STATEMENT RE DELHI UNIVERSITY (AMENDMENT BIL)L 1972

THE MINISTER OF EDUCATION, SOCIAL WELFARE AND CULTURE (PROF. S. NURUL HASAN) : Sir, I beg to make a statement in connection with the Delhi University (Amendment) Bill, 1972 and the statutes regarding College Councils made by the Executive Council of the University under the authority of the Delhi University (Amendment) Ordinance, 1972 and approved by the Visitor.

Since leave to introduce the Delhi University (Amendment) Bill, 1972 was granted by the Rajya Sabha on August 3, 1972, there have been further consultations on the subject. In view of these consultations, it is necessary to clarify that the proposed amendment of the Act is visualised as being entirely within the framework of the existing character of the University. It is aimed at an administrative reorganisation that will establish a more decentralised system of decision making and sharing of responsibilities by the academic community, help the colleges to perform their academic and other responsibilities more efficiently and expeditiously and enable the University as a whole to devote more time and energy to improve the quality of its academic work.

As may be observed, the additional Statutes already made by the Executive